

वैट बकाया माफ और जीएसटी (संशोधन) वधियक मसौदा

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों में 25,000 रुपए तक के [मूल्य वर्धति कर \(वैट\)](#) की राशि माफ करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ [GST \(संशोधन\) वधियक, 2025](#) तथा छत्तीसगढ़ बकाया राशि निपटान (संशोधन) वधियक, 2025 के प्रारूपों को भी मंजूरी दे दी है।

नोट:

मूल्य वर्धति कर (वैट): यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जो बेची गई वस्तुओं पर लगाया जाता है और [आपूर्ति शृंखला](#) के प्रत्येक चरण पर लागू होता है। यह उन वस्तुओं पर लागू होता है, जो [GST व्यवस्था](#) से बाहर हैं, जैसे [मादक पेय पदार्थ](#), [पेट्रोलियम उत्पाद](#) आदि।

मुख्य बढि

पुराने वैट बकाया माफ:

- पुराने वैट बकाये को माफ करने से 40,000 से अधिक छोटे व्यापारियों को लाभ मल्लिगा और 62,000 से अधिक लंबित मामलों के समाधान में मदद मल्लिगी, जसिसे अनुपालन बोझ और मुकदमेबाजी के लंबित मामलों में उल्लेखनीय कमी आएगी।

जीएसटी से संबंधित संशोधन वधियकों के मसौदे स्वीकृत:

- सरकार ने दो प्रमुख वधियकों के मसौदों को मंजूरी दी है:
 - छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) वधियक, 2025
 - छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज और शास्ति निपटान (संशोधन) वधियक, 2025
- दोनों वधियक 14 जुलाई 2025 से शुरू होने वाले राज्य वधिनसभा के मानसून सत्र के दौरान पेश किये गए।

मसौदे की मुख्य वशिषताएँ:

- ये वधियायी संशोधन राज्य में व्यापार को सुगम बनाने की सरकार की व्यापक रणनीतिका हसिस्सा हैं।
 - प्रस्तावित परिवर्तन [55वीं GST परिषद](#) की बैठक में लिये गए नरिणयों के अनुरूप हैं।
- मसौदा वधियक में अपीलिय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने के लिये केवल दंड वाले मामलों (जनिमें कोई कर मांग नहीं है) के लिये [अनवार्य पूर्व-जमा को 20% से घटाकर 10% करने का प्रस्ताव है।](#)
- [वाउचर की करदेयता](#) से संबंधित "आपूर्ति के समय" प्रावधान को [हटाने](#) का प्रस्ताव कयिा गया है ताक [अग्रमि नरिणय प्राधिकरण](#) के परस्पर वशिरीधी नरिणयों से उत्पन्न [भ्रम](#) को दूर कयिा जा सके तथा [स्पष्टता और एकरूपता](#) सुनिश्चित हो सके।
- एक प्रमुख संशोधन के तहत, [वशिष आरथकि कषेत्रों \(SEZ\)](#) के भीतर [वेयरहाउसिंग लेनदेन](#) को [GST ढाँचे से बाहर रखने](#) का प्रस्ताव है।
 - यह उन [सामानों](#) पर लागू होगा, जो [SEZ के गोदामों](#) में रखे रहते हैं और [बनिा भौतिक परिवहन के बार-बार व्यापार](#) में प्रयुक्त होते हैं। इसका उद्देश्य [SEZ के भीतर व्यापार दक्षता](#) को बढावा देना है।

GST परिषद

- परिचय:** GST परिषद (जो कि [अनुच्छेद 279-A](#) के अंतर्गत 101वें संवैधानिक संशोधन, 2016 द्वारा गठित एक [संवैधानिक नकियाय](#) है) द्वारा GST के कार्यान्वयन संबंधी सफिरशि की जाती है।
 - GST एक [मूल्यवर्धति \(एड वैलोरम\)](#) और [अप्रत्यक्ष कर प्रणाली](#) है, जो भारत में वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
- सदस्य:** इस परिषद में [केंद्रीय वतित मंत्री \(अध्यक्ष\)](#), [केंद्रीय राज्य मंत्री \(वतित\)](#) और प्रत्येक राज्य से एक वतित या कोई अन्य मंत्री शामिल होते हैं।

- **नरिण्यों की प्रकृति:** **22222 2222222 22222, 2022** में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि GST परिषद की सफाई **बाध्यकारी नहीं** है, क्योंकि संसद एवं राज्यों दोनों के पास GST के संबंध में **वर्धनीय शक्त** है।

वर्शैष आर्थकि क्षेत्त्र (SEZ)

- **परिचय:** SEZ एक शुल्क-मुक्त क्षेत्र है, जिसे व्यापार, शुल्क और संचालन के उद्देश्य से विदेशी क्षेत्र माना जाता है। कोई भी नजिी/सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र या राज्य सरकार या उसकी एजेंसियाँ SEZ स्थापित कर सकती हैं।
 - भारत में SEZ को पहली बार वर्ष 2000 में **विदेश व्यापार नीति** के तहत शुरू किया गया था, जिसने पहले के **नरियात प्रसंस्करण क्षेत्रों (EPZ)** की जगह ली थी। वे **SEZ अधिनियम, 2005** और **SEZ नियम, 2006** द्वारा शासित होते हैं।
- **उद्यम एवं सेवा केंद्र विकास (DESH) विधेयक, 2022** का उद्देश्य SEZ अधिनियम, 2005 को प्रतस्थापित करना तथा SEZ को अधिक अनुकूल एवं समावेशी विकास केंद्रों में परिवर्तित करना है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/waives-vat-dues-and-gst-amendment-bill-drafts>

